



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]
No. 665]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2003/श्रावण 3, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2003/SRAVANA 3, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

क्र.आ. 854(अ).— भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है, नामतः:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : (1) इस योजना को भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (योजनाओं, परिसंपत्तियों, निवेश का प्रबंधन, सलाहकारों का कार्यकाल, शुल्क, भत्ते तथा नियुक्ति की शर्तें एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 2003 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं : इस योजना में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) “अधिनियम” का अर्थ है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 ;

(ख) “सलाहकार” का अर्थ है, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति ;

- (ग) “सलाहकार बोर्ड” का अर्थ है, धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे सदस्यों वाला बोर्ड ;
- (घ) “योजना” का अर्थ है, अधिनियम की धारा 20 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना ;
- (ङ) यहां प्रयुक्त किए गए तथा योजना में परिभाषित न किए गए, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं।

3. विनिर्दिष्ट उपक्रम के कार्यों का प्रबंधन

- (1) प्रशासक (विनिर्दिष्ट उपक्रम के कार्यपालकों सहित) इस योजना के अनुबंध-क में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित योजनाओं के प्रबंधन कार्य करेगा।
- (2) परिसंपत्ति पुनर्संरचना निधि, बाल कल्याण निधि, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि तथा निवेशक संरक्षण निधि की बंद की जा चुकी योजनाओं के संबंध में निवेश/विनिवेश निर्णय सलाहकार बोर्ड के समग्र मार्गनिर्देशनाधीन प्रशासक द्वारा किए जाएंगे।
- (3) यदि प्रशासक की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिए ऊपर उप-नियम (1) तथा (2) से संबंधित मामलों में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, जहां विनिर्दिष्ट उपक्रम के हित पर पूर्वाग्रहपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है यदि सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक तक ऐसी कार्रवाई को आस्थगित किया जाता है, तो प्रशासक ऐसी कार्रवाई कर सकता है, किन्तु प्रत्येक ऐसे मामले में वह कार्रवाई करने के पश्चात यथाशीघ्र सलाहकार बोर्ड को तथा केन्द्रीय सरकार को एक लिखित रिपोर्ट देगा जिसमें की गई कार्रवाई का तथा परिस्थितियां जिनके तहत कार्रवाई की गई थी, का विवरण निहित होगा।

4. सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं, कार्यकाल, अनर्हता, पद का त्याग

- (1) सदस्य एक योग्य, सत्यनिष्ठ तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसके पास अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, बैंकिंग, वित्त, उद्योग, लोक कार्यों या प्रशासन अथवा किसी अन्य विधा, जो केन्द्रीय सरकार की राय में सलाहकार बोर्ड के लिए उपयोगी होगी, का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव या प्रदर्शित क्षमता है।

- (2) सलाहकार बोर्ड के किसी सदस्य को नियुक्त करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार यह संतुष्टि करेगी कि उस व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य स्वार्थ नहीं है जो सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर पूर्वाग्रहपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
 - (3) प्रत्येक सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा किन्तु वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
 - (4) सलाहकार बोर्ड का प्रत्येक सदस्य (तथा प्रशासक) अपना कार्यभार संभालने से पूर्व इस योजना के अनुबंध ख पर संलग्न प्रपत्र में पद की शपथ लेगा तथा पदभार ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेगा।
 - (5) कोई भी व्यक्ति सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए तथा बने रहने के लिए अनर्हक होगा :
 - (क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया हो ; अथवा
 - (ख) यदि ऐसे अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो, अथवा
 - (ग) यदि उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टता अंतर्ग्रस्त है।
 - (6) यदि कोई सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक क्रमिक बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसके द्वारा अपना पदभार त्याग दिया गया माना जाएगा तथा तब उसका पद रिक्त हो जाएगा।
5. **कार्यालय से त्यागपत्र/निष्कासन** : प्रशासक या कोई भी सलाहकार, किसी भी समय, हस्तलिखित और केन्द्रीय सरकार को संबोधित त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है :
- बशर्ते कि वह सदस्य, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, ऐसी सूचना की पावती की तिथि से एक महीने की समाप्ति तक या विधिवत् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति के पदभार ग्रहण करने तक, या अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद को धारण किए रहेगा।
6. **आकस्मिक रिक्ति** : पैरा 5 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड के किसी भी सदस्य के त्यागपत्र या निष्कासन के कारण अथवा अन्यथा हुई आकस्मिक रिक्ति के स्थान पर नई नियुक्ति की जाएगी।

7. नियुक्तियों में त्रुटियों से अधिनियम इत्यादि अमान्य नहीं :

- (1) सलाहकार बोर्ड का कोई भी अधिनियम या कार्रवाई केवल इन कारणों से अमान्य नहीं होगी -- इसके सदस्यों के किसी रिक्त स्थान के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने के कारण ; अथवा
- (2) सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण ; अथवा
- (3) सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता होने के कारण, जो मामले के गुणदोष को प्रभावित न कर रही हो।

8. वेतन और भत्ते : सलाहकार बोर्ड का प्रत्येक सदस्य ---

- (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक, जिसमें वह उपस्थित होता है, के लिए दो हजार रुपए की फीस प्राप्त करेगा ;
- (2) उसे अपने स्वयं के यात्रा खर्चों, यदि कोई हो, की पुनःपूर्ति की जाएगी और प्रतिदिन दो सौ अस्सी रुपए के विराम भत्ते का भुगतान किया जाएगा जिसकी गणना सलाहकार के अपने मुख्यालय से अथवा यदि यात्रा किसी अन्य स्टेशन से की गई हो, तो ऐसे स्टेशन से प्रस्थान के समय से की जाएगी।
- (3) किसी सलाहकार को, जो केन्द्रीय सरकार का अधिकारी है, सरकारी अधिसूचना संख्या का.आ.43(अ) दिनांक 15.1.2003 के अनुसार यात्रा और विराम भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

9. सलाहकार बोर्ड की बैठकें

- (1) प्रशासक सलाहकार बोर्ड की बैठकों का अध्यक्ष होगा और सलाहकार मंडल की बैठकों का संयोजन और अध्यक्षता करेगा जो साधारणतया उसके कार्यालय में अथवा भारत में किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएंगी।
- (2) यह बोर्ड अपने व्यवसाय के कार्यचालन के लिए समय-समय पर अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (3) सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यचालन की प्रक्रिया में कुछ भी निहित होने के बावजूद सलाहकार बोर्ड के न्यूनतम दो सलाहकारों द्वारा दिए गए नोटिस पर सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी।
- (4) यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ सलाहकार बोर्ड की बैठकों का संयोजन करना आवश्यक है तो सलाहकार बोर्ड ऐसी बैठक का संयोजन करेगा।

- (5) साधारणतया, बैठक के संयोजन के लिए कम से कम सात पूर्ण दिनों का नोटिस दिया जाएगा। अत्यावश्यकता की स्थिति में यह बैठक कम से कम चौबीस घंटे के नोटिस पर बुलाई जा सकती है।
 - (6) प्रशासक सहित तीन सदस्यों से कोरम बनेगा। बहुमत की राय पर बोर्ड निर्णय लेगा।
 - (7) कोई सदस्य, जिसका बोर्ड की कार्यसूची के किसी भी मामले में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक हित है, प्रकटीकरण करेगा और उस मामले के बारे में विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।
 - (8) प्रशासक अथवा उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई सलाहकार प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का परिचालन सूचना और पुष्टि हेतु बैठक के दो दिन के भीतर प्रत्येक सलाहकार को करेगा।
 - (9) सलाहकार बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम छः बार होगी और दो बैठकों के बीच अंतराल पचहत्तर दिन से अधिक का नहीं होगा।
10. **उधार शक्ति :** प्रशासक ऐसे सभी कार्य या वस्तुएं ले सकता है जो अधिनियम की धारा 10 के तहत उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अनुषंगी या परिणामी हैं।
11. **व्याख्या :** यदि इस योजना के किसी उपबंध की व्याख्या से जुड़ा कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो उसे केन्द्र सरकार के निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा, जो अंतिम होगा।

[फा. सं. 5/6/2003-यूटीआई एवं जेपीसी]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

स्कीम का अनुबंध क

[देखिए धारा 3(1)]

लेन-देन धनशोधन संबंधी अपेक्षाओं द्वारा शासित किए जाएंगे ।

प्राथमिक बाजार (इक्विटी) : इसमें आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), खुली पेशकश, निजी तौर पर, खरीद, अधिकार (राइट्स), वापस खरीद पेशकश (बाजार प्रचालनों के जरिए किए प्रचालनों से इतर) वारंट रूपान्तरण इत्यादि शामिल हैं ।

प्राथमिक बाजार	निम्नलिखित द्वारा अनुशंसित	निम्नलिखित द्वारा पुनरीक्षित	अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी
(क) इक्विटी शेयरों की खरीद : (आईपीओ, तरजीही आबंटन, राइट्स, हामीदारी इत्यादि)	संबंधित स्कीम के निधि प्रबंधक	संबंधित डीएफएम के प्रमुख	ईडी और प्रशासक से युक्त समिति : 40 करोड़ ₹ तक । सलाहकार बोर्ड : 40 करोड़ ₹ से अधिक के सभी प्रस्ताव ।
(ख) इक्विटी शेयरों की बिक्री : (खुली पेशकश, वापस खरीद (द्वितीयक बाजार के जरिए की गई बिक्री से इतर) इत्यादि)	संबंधित स्कीम के निधि प्रबंधक	संबंधित डीएफएम के प्रमुख	ईडी और प्रशासक से युक्त समिति : 40 करोड़ ₹ तक । सलाहकार बोर्ड : 40 करोड़ ₹ से अधिक के सभी प्रस्ताव ।

प्राथमिक बाजार के सभी इक्विटी लेन-देनों के संबंध में, निधि लेखा विभाग द्वारा निधियों के संवितरण/इक्विटी शेयरों की पेशकश की सहायता निधि प्रबंधकों की गई स्कीम वार सिफारिश और उसका उपर्युक्त के अनुसार अनुमोदन किए जाने के जरिए की जाएगी ।

अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी निवेश/निर्निहितीकरण पर केवल तभी विचार करेगा यदि संबंधित निधि प्रबंधकों ने उसकी सिफारिश की हो ।

द्वितीयक बाजार (इक्विटी) : द्वितीयक बाजार के इक्विटी लेन-देन (इन्डेक्स निधियों के तहत किए लेन-देनों के अलावा) निधि प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों के आधार पर यूटीआई एएमसी की "डीलिंग रूम" (इक्विटी) द्वारा किए जाएंगे तथा नीचे निर्दिष्ट की गई शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित किए जाएंगे।

भाग (क) और (ख) में प्रत्येक निधि द्वारा किए जाने वाले लेन-देनों के लिए निधि प्रबंधकों को किए जाने वाले शक्तियों के प्रत्यायोजन की सूची दी गई है। भाग (ग) समूचे तौर पर यूटीआई (I) के लेन-देनों के निष्पादन से संबंधित है। ऐसे निष्पादनों के लिए सीमाएं ऊपर भाग (ग) में निर्धारित की गई हैं।

(क) इन्डेक्स निधियों को छोड़कर सभी स्कीमों के संबंध में : निधि स्तर पर समग्र सीमा

द्वितीयक बाजार लेन-देन (इक्विटी)	अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी			
	निधि प्रबंधक @	डीएफएम का प्रमुख	प्रशासक	सलाहकार बोर्ड
एक दिन में एक ही स्कीम द्वारा किए गए लेन-देन का कुल मूल्य	10 करोड़ ₹ अथवा संबंधित निधियों की मात्रा के 5% से अधिक नहीं। जो भी कम हो।	20 करोड़ ₹ अथवा संबंधित निधियों की मात्रा के 7.5% से अधिक नहीं। जो भी कम हो।	40 करोड़ ₹ अथवा संबंधित निधियों की मात्रा के 10% से अधिक नहीं। जो भी कम हो।	प्रत्यायोजित प्राधिकार की सीमा से अधिक हुई सभी शक्तियां

(ख) निधि में कम्पनीवार सीमा

द्वितीयक बाजार लेन-देन (इक्विटी)	• अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी			
	निधि प्रबंधक @	डीएफएम का प्रमुख	प्रशासक	सलाहकार बोर्ड
(ख) एक कंपनी में एक ही स्कीम द्वारा लेन-देन किए गए शेयरों की कुल संख्या/मूल्य	5 करोड़ ₹ अथवा	10 करोड़ ₹ अथवा	20 करोड़ ₹ अथवा	प्रत्यायोजित प्राधिकार की सीमा से अधिक हुई सभी शक्तियां

	एक कंपनी के लिए निधि के 2% से अधिक नहीं अथवा उक्त कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 0.5% से अधिक नहीं जो भी कम हो ।	एक कंपनी के लिए निधि के 5% से अधिक नहीं अथवा उक्त कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 1% से अधिक नहीं जो भी कम हो ।	एक कंपनी के लिए निधि के 5% से अधिक नहीं अथवा उक्त कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 1% से अधिक नहीं जो भी कम हो ।	
--	---	---	---	--

@ : इस पर संबंधित ग्रेड बी अथवा ऊपर की श्रेणी के डीएफएम के कम से कम दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिनमें से कम से कम एक इस स्कीम का नामित निधि प्रबंधक हो ।

(ग) व्यापार मूल्य, निधि की मात्रा के परिकलन के लिए पिछले दिन के समापन मूल्य को ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) उपरिलिखित सीमाओं में उस दिन अंतर-स्कीम अंतरण के माध्यम से एकल स्कीम द्वारा किए गए सभी इक्विटी लेन-देन भी शामिल होंगे ।

द्वितीयक बाजार में कार्य निष्पादन

द्वितीयक बाजार व्यापार (इक्विटी)	कार्य निष्पादन के लिए अनुमति		
	जी0एम0	प्रशासक	सलाहकार बोर्ड
किसी कंपनी के शेयरों की संख्या के संदर्भ में यूटीआई द्वारा समेकित आधार पर एक दिन में किया गया कुल लेन-देन	जीएम (द्वितीयक बाजार का डीलिंग इनचार्ज) : कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 1% तथा 1% से अधिक 3% तक ।	सीजीएम/ईडी (द्वितीयक बाजार का डीलिंग इनचार्ज) : कंपनी की चुकता पूंजी का 3% से अधिक तथा 5% तक ।	कंपनी की चुकता पूंजी के 5% से अधिक

रिपोर्टिंग

प्राथमिक बाजार लेनदेन

प्राथमिक बाजार के सभी इक्विटी संबंधी लेन देनों की सूचना डीलिंग विभाग (प्राथमिक बाजार) द्वारा उसी दिन सीजीएम/ईडी (डीलिंग विभाग) तथा प्रशासक को दी जानी चाहिए ।

प्राथमिक बाजार में इक्विटी शेयरों की खरीद तथा इक्विटी शेयरों की बिक्री संबंधी समस्त जानकारी सलाहकार बोर्ड को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी ।

द्वितीय बाजार लेनदेन

- (क) द्वितीयक बाजार में निधि द्वारा किए गए सभी लेनदेनों की सूचना दैनिक आधार पर डीएफएम के प्रमुख तथा सीजीएम/डीएफएम के ईडी इनचार्ज को दी जाती है ।
- (ख) दिए गए आदेशों के संबंध में डीलिंग विभाग (द्वितीयक बाजार) एक रिपोर्ट दैनिक आधार पर तैयार करता है जिसे सीजीएम/ईडी (डीलिंग) तथा प्रशासक को सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है ।
- (ग) द्वितीयक इक्विटी बाजार के सभी लेनदेनों तथा ब्रोकर-वार कारोबार का सारांश अनुवर्ती बैठक में सलाहकार बोर्ड की सूचना हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

नियंत्रण तथा उपचारात्मक कार्रवाई

ऊपर सूचीबद्ध शक्तियों के प्रत्यायोजन का नियंत्रण प्रणाली संचालित पद्धति द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु स्थापित किए जाते हैं ।

यदि संयोगवश किसी स्तर पर कोई उल्लंघन हो अर्थात् लेनदेन की राशि प्रत्यायोजित शक्ति से अधिक हो जाए तो इसकी सूचना तत्काल उच्चतर अधिकारी (जिसके पास ऐसे लेन देन के लिए प्रत्यायोजित शक्ति है) को दी जाती है तथा इसका कारण बताते हुए उक्त उल्लंघन के लिए अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है ।

प्रत्यायोजित शक्ति को प्रतिबंधित करने का अधिकार

यदि स्थिति की मांग हो तो उपरोक्त प्रत्यायोजन का विचार किए बिना उच्चतर स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, प्रशासक किसी विशेष निधि प्रबंधक/प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किसी विशेष निधि अथवा सभी निधियों के लिए लिखित निदेश जारी कर सकता है।

इक्विटी को छोड़कर अन्य निवेशों के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन (ऋण)

वर्तमान में द्वितीयक बाजार संबंधी लेनदेनों के मामले में निवेश डीलिंग विभाग-डीओडी ऋण अनुभाग के माध्यम से तथा प्राथमिक बाजार संबंधी लेनदेनों के मामले में डीलिंग विभाग प्राथमिक बाजार अनुभाग के माध्यम से किया जाता है। संबंधित अनुभागों द्वारा निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

प्राथमिक बाजार ऋण प्रपत्रों के मामले में, डीओडी को जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं वह उन्हें निधि प्रबंधन विभाग-डीएफएम (ऋण-I ऋण-II तथा यूएस-64) को भेज देता है।

डीओडी इस प्रस्ताव पर, डीएफएम की राय प्राप्त होने पर, इसे ईडी तथा प्रशासक से युक्त समिति के पास भेजता है। इस प्रस्ताव पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की स्थिति में पीएमआईसी इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रशासक के पास भेजने की सिफारिश करता है।

द्वितीयक बाजार ऋण प्रपत्रों के मामले में, डीओडी अपने स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को निधि प्रबंधन विभाग (ऋण-I, ऋण-II तथा यू.एस.-64) के पास भेजता है। डीओडी इस प्रस्ताव पर, डीएफएम की राय प्राप्त होने पर इसे प्रशासक के पास अनुमोदन के लिए भेजता है।

क) आंतरिक दिशानिर्देशों के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रत्यायोजन ऋण निवेशों जैसे जी-सेक्स, कार्पोरेट डिबेंचर्स (जिसमें एफसीडी, एनसीडी, पीसीडी, ओएफसीडी आदि शामिल हैं), प्रतिभूतिकृत ऋण, तरजीही शेयर इत्यादि (इक्विटी के अलावा अन्य सभी निवेश) के लिए है।

1. प्राथमिक बाजार निवेश (ऋण-सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) :

इसमें आईपीओ, निजी स्थापन, पुट ऑप्शन का प्रयोग, राइट इश्यु में अभिदान आदि (द्वितीयक बाजार लेनदेन के अलावा अन्य सभी लेनदेन) शामिल है।

खरीद : प्रयोज्य शक्तियां प्रति कंपनी प्रतिदिन होंगी।

कंपनी/प्रपत्र रेटिंग	संवीक्षा	निम्न के द्वारा अनुशंसित	अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी
एए- और उससे ऊपर (या कोई समतुल्य रेटिंग) तथा केवल 'एएए' रेटिंग वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	टिप्पणी * द्वारा प्राथमिक बाजार संभाग	निधि प्रबंधक	<p>ईडी तथा प्रशासक: निधि प्रबंधक की सिफारिश पर सभी स्कीमों के लिए कुल मिलाकर 40 करोड़ रूपए तक</p> <p>सलाहकार बोर्ड : ईसी/बोर्ड द्वारा सभी स्कीमों के संबंध में निधि प्रबंधक तथा पीएमआईसी की सिफारिश पर 40 करोड़ रूपए से अधिक की राशि ।</p>

	कंपनी/प्रपत्र रेटिंग	प्रत्यायोजन
खरीद	ए + तथा उससे नीचे (अथवा कोई समतुल्य रेटिंग) तथा एएए से कम की रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	<p>सलाहकार बोर्ड सभी स्कीमों के लिए निधि प्रबंधक तथा ईडी तथा प्रशासक से युक्त समिति की सिफारिश पर</p>
	कंपनी/प्रपत्र रेटिंग	प्रत्यायोजन
बिक्री	रेटिंग का ख्याल किए बिना ऋण पूर्व अदायगी की पुनर्खरीद आदि जैसे सभी लेनदेन	<p>निधि प्रबंधक तथा आंतरिक समिति की सिफारिश पर</p> <p>प्रशासक : 40 करोड़ रूपए तक।</p> <p>सलाहकार बोर्ड : 40 करोड़ रूपए से अधिक की राशि ।</p>
	प्रतिभूतियों पर पुट ऑप्शन	<p>निधि प्रबंधक तथा आंतरिक समिति की सिफारिश पर</p> <p>प्रशासक : 40 करोड़ रूपए तक।</p> <p>सलाहकार बोर्ड : 40 करोड़ रूपए से अधिक की राशि ।</p>

देनदारी मानदंड

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सभी भावी निवेशों के लिए एक एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में देनदारी को, अद्यतन लेखापरीक्षा किए गए तुलनपत्र के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अधिकतम निवल मूल्य तक सीमित रखा जाए। इस प्रयोजनार्थ निवल मूल्य को निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता है :-

निवल मूल्य = चुकता शेयर पूंजी + प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर) - बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय- संचित हानियाँ, यदि कोई हैं।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश में आवासीय वित्त कंपनियों (जिनके लिए अलग मानदंड हैं) तथा बैंकों द्वारा जारी टियर-II बांडों में किया गया निवेश शामिल नहीं है।

2. द्वितीयक बाजार निवेश (ऋण-सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न):

खरीद : प्रयोज्य अधिकार प्रति कंपनी प्रतिदिन होंगे

कंपनी/प्रपत्र रेटिंग	संवीक्षा	निम्न के द्वारा अनुशंसित	अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी
ए ए- तथा उससे ऊपर (अथवा कोई समतुल्य रेटिंग) ** तथा केवल 'एएए' क्रेडिट रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	द्वितीयक बाजार खंड (ऋण) द्वारा कार्यालय टिप्पणी (ज्ञापन के भाग ख में ब्यौरा दिया गया है)	निधि प्रबंधक	<p>निधि प्रबंधक: किसी योजना के प्रबंध के अधीन परिसम्पत्तियों के 2% तक अथवा किसी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। कार्यकारी निदेशक एवं प्रशासक से युक्त समिति निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर, किसी योजना के प्रबंध के अधीन परिसम्पत्तियों के 5% तक अथवा किसी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए जो भी कम हो। सलाहकार बोर्ड : निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर किसी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक</p>
ए + तथा उससे (अथवा कोई समतुल्य	द्वितीयक बाजार खंड (ऋण) द्वारा विस्तृत	निधि प्रबंधक	सलाहकार बोर्ड

रेटिंग) तथा एएए से कम की रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	टिप्पणी ****		निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर .
निवेश-भिन्न श्रेणी (बिना रेटिंग वाले अन्य प्रपत्र)	द्वितीयक बाजार खंड (ऋण) **** द्वारा विस्तृत टिप्पणी (ज्ञापन के भाग ख में ब्यौरा दिया गया है)	निधि प्रबंधक	सलाहकार बोर्ड निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर

बिक्री : प्रयोज्य शक्तियां प्रति कंपनी प्रतिदिन होंगी

कंपनी/प्रपत्र रेटिंग	संवीक्षा	निम्न के द्वारा . अनुशंसित	अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी
ए ए- तथा उससे ऊपर (अथवा कोई समतुल्य रेटिंग) **	द्वितीयक बाजार खंड द्वारा कार्यालय टिप्पणी (ज्ञापन के भाग ख में ब्यौरा दिया गया है)	निधि प्रबंधक	<p>निधि प्रबंधक: किसी योजना के प्रबंध के अधीन परिसम्पत्तियों के 2% तक अथवा किसी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। कार्यकारी निदेशक एवं प्रशासक से युक्त समिति निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर, किसी योजना के प्रबंध के अधीन परिसम्पत्तियों के 5% तक अथवा किसी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए जो भी कम हो।</p> <p>सलाहकार बोर्ड : निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर किसी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक</p>
ए + तथा उससे नीचे (अथवा अन्य समतुल्य रेटिंग) तथा सभी रेटिंग वाली	द्वितीयक बाजार खंड (ऋण) **** द्वारा विस्तृत टिप्पणी	निधि प्रबंधक	<p>निधि प्रबंधक: किसी योजना के प्रबंध के अधीन परिसम्पत्तियों के 2% तक अथवा किसी योजना के लिए 5 करोड़</p>

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियां			<p>रुपए जो भी कम हो। कार्यकारी निदेशक एवं प्रशासक से युक्त समिति निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर, किसी योजना के प्रबंध के अधीन परिसम्पत्तियों के 5% तक अथवा किसी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए जो भी कम हो। सलाहकार बोर्ड : निधि प्रबंधक की अनुशंसा पर किसी योजना के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक</p>
--	--	--	---

उल्लिखित राशियां अंकित मूल्य में हैं, सिवाय बट्टाकृत बांडों के जिनमें इस प्रयोनार्थ अधिग्रहण लागत पर विचार किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों की खरीद से संबंधित प्रस्ताव की स्थिति में इसे अनुमोदनार्थ सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

निर्णय लेते समय जिस प्राप्ति पर सिफारिश की जाती है यदि वह तदनुरूपी रेटिंग और मूल्यनिर्धारण के लिए प्रयोग की गई मैट्रिक्स में संशोधित अवधि में उल्लिखित प्राप्तियों की तुलना में खरीद/बिक्री के लिए कम/अधिक है तो प्रत्यायोजन के अनुसार इसे अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

*** द्वितीयक बाजार अनुभाग वित्तीय विश्लेषण करता है, चूक करने की स्थिति दर्शाता है, प्राथमिक बाजार निवेशों के लिए विहित वित्तीय मानदंडों और विनियामक अपेक्षाओं के पालन को निर्दिष्ट करता है और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करता है।

द्वितीयक बाजार में निष्पादन (यूटीआई-1 के लिए समग्र रूप में)

द्वितीयक बाजार के लेन-देन (इक्विटी के अलावा)	एजीएम	जीएम	ईडी
यूटीआई-1 के लिए समग्र रूप में प्रति कंपनी प्रतिदिन	10 करोड़ रुपए	25 करोड़ रुपए	25 करोड़ रुपए ये अधिक

1. सरकारी प्रतिभूतियां :

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में प्राथमिक एवं द्वितीयक रूट के माध्यम से निवेशों के लिए द्वितीयक बाजार निवेश (ऋण) के अधीन उल्लिखित राशि की सीमा का दस गुणा प्रयोज्य होगा जबकि उसी प्रबंधन के अधीन आस्तियों की प्रतिशत सीमाएं वही रहेंगी

केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां प्रतिदिन : प्राथमिक और द्वितीयक बाजार : खरीद एवं बिक्री मिश्रित

अनुमोदन प्राधिकारी
निधि प्रबंधक : स्कीम प्रबंधन के अधीन आस्तियों के 4 प्रतिशत तक अथवा स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो।
कार्यकारी निदेशक और प्रशासक से युक्त समिति निधि प्रबंधक की सिफारिश पर, स्कीम प्रबंधन के अधीन आस्तियों के 10 प्रतिशत तक अथवा स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो।
सलाहकार बोर्ड निधि प्रबंधक की सिफारिश पर स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक

राज्य सरकार प्रतिभूतियों में प्राथमिक एवं द्वितीयक रूट के माध्यम से निवेशों के लिए द्वितीयक बाजार निवेश (ऋण) के अधीन उल्लिखित राशि की सीमा का पांच गुणा प्रयोज्य होगा जबकि प्रबंधन के अधीन आस्तियों की प्रतिशत सीमा वही रहेगी।

राज्य सरकार प्रतिभूतियां प्रतिदिन :

अनुमोदन प्राधिकारी
निधि प्रबंधक : स्कीम प्रबंधन के अधीन आस्तियों के 4 प्रतिशत तक अथवा स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो।
कार्यकारी निदेशक और प्रशासक से युक्त

समिति

निधि प्रबंधक की सिफारिश पर, स्कीम प्रबंधन के अधीन आस्तियों के 10 प्रतिशत तक अथवा स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो।

सलाहकार बोर्ड

निधि प्रबंधक की सिफारिश पर स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक

निधि प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि सभी निवेश संबंधी निर्णय, प्रत्येक निधि के नकदी मूल्य, निवेश उद्देश्यों, आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा नियामक प्रतिबंधों पर आधारित हों।

अन्य

परिसंपत्तियों के अंतःस्कीम अंतरण, परिसंपत्तियों के द्वितीयक बाजार अंतरण के समान हैं जो वर्तमान मूल्यांकनों/कीमतों पर आधारित हैं। वे यूटीआई-1 के लिए कोई नया देनदारी सृजित नहीं करते हैं। अतः एए--तथा इससे उच्च रेटिंग वाली कंपनियों और 'एएए' रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु अंतः स्कीम अंतरणों के लिए प्रत्यायोजन, द्वितीयक बाजार कार्यकलापों के मामले में लागू प्रत्यायोजनों के समान होंगे। 'एएए' की रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से भिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा निवेश ग्रेड वाले ए+ श्रेणी के कागजातों को प्रशासक द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) निर्णय प्रक्रिया/निवेश संबंधी निर्णयों का प्रलेखन

विवरण निवेश नीतियों, मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा जोखिम नियंत्रण ढांचा संबंधी नियम पुस्तिका के अध्याय-3 के अनुसार।

(ग) रिपोर्टिंग :

किए गए निवेश के बारे में प्राथमिक बाजार संभाग/द्वितीयक बाजार संभाग द्वारा एक रिपोर्ट कार्यकारी निदेशकों एवं प्रशासक को दैनिक आधार पर सूचनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं। इसका संक्षिप्त विवरण भी नियमित आधार पर सलाहकार बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(घ) नियंत्रण तथा सुधारात्मक कार्यवाई :

उपरोक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रणाली संचालित पद्धति (जब भी लागू की जाए) के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है जिसके माध्यम से शक्तियों के प्रत्यायोजन के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं संतुलन की व्यवस्था की जाती है।

यदि किसी कारणवश किसी भी स्तर पर अननुपालन होता है अर्थात् कार्यसम्पादन की राशि, प्रत्यायोजित प्राधिकार से अधिक होती है तो उसे तुरंत सक्षम प्राधिकारी को अनुसमर्थन हेतु सूचित किया जाता है।

अनुबंध-‘ख’

निष्ठा एवं गोपनीयता संबंधी घोषणा

[खंड 4(4) देखें]

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम (विनिर्दिष्ट उपक्रम) के प्रशासक या प्रशासक के सलाहकार के रूप में मेरे लिए अपेक्षित कर्तव्यों तथा उक्त विनिर्दिष्ट उपक्रम में मेरे द्वारा धारित पद से जुड़े कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार निष्पादित करूंगा।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं विनिर्दिष्ट उपक्रम के कार्यकलापों अथवा उक्त विनिर्दिष्ट उपक्रम के कार्य से संबंधित किसी व्यक्ति के कार्यकलापों के बारे में किसी अनधिकृत व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दूंगा और न ही उसे सूचित किए जाने की अनुमति दूंगा ; न ही विनिर्दिष्ट उपक्रम के स्वामित्व में या उसके कब्जे में तथा उक्त विनिर्दिष्ट उपक्रम के व्यवस्था से या उक्त विनिर्दिष्ट उपक्रम के साथ लेनदेन करने वाले किसी व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित किन्हीं पुस्तिकाओं या दस्तावेजों की जांच करने या उस तक पहुंचने की अनुमति ऐसे किसी व्यक्ति को दूंगा।

(हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

20886I/03—(3)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2003

S. O. 854(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 read with Sub-section (2) of section 9 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (58 of 2002), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. **Short Title and Commencement.** - (1) This Scheme may be called the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (Management of schemes, Assets, Investment, term of office, fees, allowances and conditions of appointment of Advisers and Miscellaneous Provisions) Scheme, 2003.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In this Scheme, unless the context otherwise requires, —
(a) “Act” means the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002;
(b) “Adviser” means a person appointed as a member of the Board of Advisers under Sub-section (1) of Section 9 of the Act;
(c) “Board of Advisers” means a Board consisting of such members appointed by the Central Government under Sub-section (1) of Section 9;
(d) “Scheme” means the scheme made by the Central Government under Section 20 of the Act;
(e) Words and expressions used herein and not defined in this Scheme but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Management of the Affairs of the Specified Undertaking:**
(1) The Administrator (including the executives of the Specified Undertaking) shall transact the management functions of the schemes mentioned in Schedule I of the Act in accordance with the procedures laid down in Annex A to this Scheme.
(2) The investment/dis-investment decisions in respect of Asset Reconstruction Fund, Children Welfare Fund, Senior Citizen Welfare Fund, Rajlakshmi Women Welfare Fund and Investor Protection Fund Terminated Schemes shall be taken by the Administrator under the overall guidance of the Board of Advisers.
(3) If the Administrator is of the opinion that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action in matters relating to sub rule (1) and (2) above, where the interest of the specified undertaking may be prejudicially affected if such action is deferred until after the next meeting of the Board of Advisers, the Administrator may take such action, but in every such case, he shall as soon as may be after the action is taken, make a written report to the Board of Advisers and to the Central Government containing a statement of the action taken and circumstances under which it was taken.
4. **Qualifications, Terms of office, Disqualification, Vacation of office of members of the Board of Advisers:**
(1) The Member shall be a person of ability, integrity and standing who has adequate knowledge or experience or shown capacity in dealing with the problems relating to economics, law, commerce, banking, finance, industry, public affairs or administration or in any other discipline which in the opinion of the Central Government shall be useful to the Board of Advisers.
(2) Before appointing any member of the Board of Advisers, the Central Government shall satisfy itself that the person does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as member.
(3) Every member shall hold office for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, but shall be eligible for reappointment.
(4) Every Member of Board of Advisers (and Administrator) shall before entering upon his office make and subscribe to an oath of office and of secrecy in Form at Annex B to this scheme before assuming the office.
(5) A person shall be disqualified for being appointed as, and for being an Adviser.—
(a) if he has at any time been adjudicated as insolvent; or
(b) if he has been found to be unsound mind and stand so declared by a competent court; or
(c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude.

(6) If an Adviser is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

5. **Resignation/Removal from Office:** The Administrator or any Adviser may by writing under his hand and addressed to the Central Government resigns his office at any time:

Provided that the member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of one month from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

6. **Casual Vacancy:** A casual vacancy caused by the resignation or removal of any member of the Board of Advisers under para 5 or otherwise shall be filled by fresh appointment.

7. **Defects in appointments not to invalidate acts etc.:**

(1) No act or proceedings of the Board of Advisers shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy among its members or any defect in the constitution thereof; or

(2) Any defect in the appointment of a person acting as a member of the Board of Advisers; or

(3) Any irregularity in the procedure of the Board of Advisers not affecting the merits of the case.

8. **Salary and Allowances:** Every member of a Board of Advisers shall. —

(1) receive a fee of two thousand rupees for each Board meeting which he attends;

(2) be reimbursed his own actual travelling expenses, if any, and shall be paid halting allowance of two hundred eighty rupees every day reckoned from the time of departure of the Adviser from his headquarters or if the journey is made from another station, from such station;

(3) An Adviser who is an officer of the Central Government shall be paid travelling and halting allowances in accordance with Government Notification No. S.O. 43(E) dated 15-1-2003.

9. **Meetings of the Board of Advisers:**

(1) The Administrator shall be the Chairperson of the meetings of the Board of Advisers and shall convene and preside over the meetings of the Board of Advisers which may be held ordinarily at his office or at any other place in India.

(2) The Board shall be free to frame its own procedure for transaction of its business from time to time.

(3) Notwithstanding anything contained in the procedure of transaction of business of meetings of the Board of Advisers, on the notice given by minimum two Advisers of the Board of Advisers, a meeting of the Board of Advisers shall be convened.

(4) If the Central Government is of the opinion that it is necessary to convene the meetings of the Board of Advisers for the purpose of carrying out the provisions of the Act, the Board of Advisers shall convene the meeting as such.

(5) Ordinarily, a notice of not less than seven clear days shall be given for convening the meeting. In exigencies, the meeting could be convened at a notice of not less than twenty four hours.

(6) Three members, including the Administrator, shall constitute a quorum. The Board shall take decision based on opinion of majority.

(7) Any member who has a direct or indirect pecuniary interest on any of the matter in the agenda of the Board shall disclose and shall not take part in the deliberation or decision with respect to that matter.

(8) The Administrator or any Adviser authorised in his absence by the Central Government shall circulate the proceedings of each meeting for information and confirmation of each Adviser within two days of the meeting.

(9) The Board of Advisers shall meet at least six times a year, and the gap between the two meetings shall not be more than seventy five days.

10. **Borrowing Power :** The Administrator may take all such acts or things as may be incidental to or consequential upon the discharge of his functions under Section 10 of the Act.

11. **Interpretation:** If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of this Scheme, the same shall be referred to the decision of Central Government, which shall be final.

[F. No. 5/6/2003-UTI & JPC]

U.K. SINHA, Jt Secy.

Annex A to the Scheme

[see section 3(1)]

Transactions shall be guided by the redemption requirements.

PRIMARY MARKET (EQUITY) : Includes IPOs, Open offers, private placement, rights, buyback offers (other than through market operations), warrant conversions, etc.

Primary Market	Recommended by	Vetting by	Approving authority
(a) Purchase of Equity Shares : (IPOs, preferential allotment, rights, underwriting etc).	Fund Managers of the respective scheme	The Head of Respective DFM	Committee consisting of ED & Administrator : Upto Rs 40 crores. Advisory Board : All the proposals above Rs. 40 crs.
(b) Sale of Equity Shares : [open offers, buybacks (other than through secondary market) etc.]	Fund Managers of the respective scheme	The Head of Respective DFM	Committee consisting of ED & Administrator : Upto Rs 40 crores Advisory Board : All the proposals above 40 crores.

For all primary market equity transactions, the disbursement of funds/tendering of equity shares by Department of Fund Accounts will be supported by scheme-wise recommendation of fund managers and approval thereof as above.

Approving authority would consider the investment/divestment only if the same is recommended by the concerned fund managers.

SECONDARY MARKET (EQUITY) : Secondary market equity transactions (excepting transactions under index funds) will be carried out by the Dealing Room (Equity) of UTI AMC based upon requisition notes originated by Fund Managers and approved as per the delegation of powers specified below.

Sections (A) and (B) list down the delegation of power to fund managers for transactions to be undertaken by each fund. Section (C) refers to the execution of transactions of the UTI-I as a whole. The limits for such executions have been set out in section (C) above.

(A) FOR ALL SCHEMES except INDEX FUNDS :**Overall Limit at Fund Level**

Secondary Market Transaction (Equity)	* Approving Authority			
	Fund Manager@	Head of the DFM	Administrator	Advisory Board
Total value of transaction by a single scheme in one day	Rs 10 crores	Rs 20 crores	Rs 40crores	All powers in excess of the delegated authority
	OR	OR	OR	
	Not more than 5 % of the fund size of the respective funds	Not more than 7.5% of the fund size of the respective funds	Not more than 10% of the fund size of the respective funds	
	Whichever is lower	Whichever is lower	Whichever is lower	

(b) Company wise limit in a fund

Secondary Market Transaction (Equity)	Fund Manager@	* Approving Authority		
		Head of the DFM	Administrator	Advisory Board
(b) Total number of shares/value transacted by a single scheme in one day in one company	*Rs 5 crores OR Not more than 2% of fund for one company OR Not more than 0.5% of paid up equity capital of the said company, Whichever is lower	Rs 10 crores OR Not more than 5% of fund for one company OR Not more than 1% of paid up equity capital of the said company Whichever is lower	Rs 20 crores OR Not more than 5% of fund for one company OR Not more than 1% of paid up equity capital of the said company, Whichever is lower	All powers in excess of the delegated authority

@: To be signed by atleast two officers of the respective DFM's of Grade B and above, of which atleast one is the designated Fund Manager of the scheme.

(c) For calculation of transaction value, fund size etc., the closing price of previous day is considered.

(d) Above-mentioned limits will also include all the equity transactions done by a single scheme through inter-scheme transfer on that day.

EXECUTION IN SECONDARY MARKET

Secondary Market Transaction (Equity)	* Approval for Execution		
	GM	Administrator	Advisory board
Total transaction in terms of number of shares of a company in a day by UTI on consolidated basis	GM (in-charge of Dealing- Secondary market) : 1% & above 1% upto 3% of the paid up equity capital of the company	CGM/ ED (in-charge of Dealing- Secondary market) : above 3% & upto 5% of the paid up equity capital of the company	More than 5% of the paid up equity capital of the company

REPORTING**PRIMARY MARKET TRANSACTIONS :**

All the primary market equity transactions should be reported to the CGM/ED (Dept of Dealing) and Administrator on the same day by Dept of Dealing (Primary Markets).

Report on all primary market purchase of equity shares and sale of equity shares will be placed to Advisory Board meeting for information.

SECONDARY MARKET TRANSACTIONS

(a) All the transactions in the secondary market by a fund are reported to Head of DFM & CGM/ED in-charge of the DFM on a daily basis.

(b) Department of Dealing (Secondary market) prepares on daily basis a report on orders placed which are forwarded to CGM/ED (Dealing) and Administrator for information.

- (c) Summary of all secondary equity market transactions and broker-wise business are placed for the information of Advisory Board in the subsequent meeting.

CONTROL AND CORRECTIVE ACTIONS

The above listed delegation of power are controlled through the system driven mechanism whereby checks and balances are established to ensure strict adherence to delegation of power.

If by any chance, there is a violation at any level i.e. transacted amount exceeds the delegated authority, then it is immediately reported to the authority of higher level (who has the delegation for such transaction) along with explanation to seek ratification of the said violation.

AUTHORITY TO RESTRICT THE DELEGATED POWER

If the situation warrants, Administrator may direct in writing either a particular Fund or all the funds managed by a particular fund manager/s, to seek the approval of the higher level irrespective of the above delegation.

DELEGATION OF POWER FOR INVESTMENTS OTHER THAN EQUITY (DEBT):

Currently, the investments in debt (all instruments other than equity) takes place through Department of Dealing-DOD Debt Section in case of secondary market transactions and through Department of Dealing Primary Market Section in case of primary market transactions. The respective sections will obtain the approvals of the appropriate authority, by following the procedure mentioned below.

In the case of primary market debt instruments the DOD sends the proposals received at their end to the Department of Fund Management-DFM (Debt-I, Debt-II and US 64). The DOD, on getting the DFM's interest on the proposal, sends the same to the Committee comprising of ED and Administrator. The PMIC, in case a positive view is taken on the proposal, recommends the proposal to the Administrator for approval.

In the case of secondary market debt instruments the DOD sends the proposals received at their end to the Department of Fund Management (Debt-I, Debt-II and US 64). The DOD, on getting the DFM's interest on the proposal, sends the same to the Administrator for approval.

(A) The following delegation, as a part of internal guidelines, is for debt investments like G-Secs, Corporate debentures (including FCDs, NCDs, PCDs, OFCDs etc.), securitised debt, preference shares etc. (all investments other than equity).

1. PRIMARY MARKET INVESTMENT (Debt - other than Govt. securities)

Includes IPOs, Private placements, Exercising Put option, Subscription to Rights issue etc. (all transactions other than secondary market transactions).

Purchases : The powers applicable will be per company per day

Company/ Instrument Rating	Scrutiny	Recommended by	Approving authority
AA- and above (or any equivalent rating) and NBFCs rated only 'AAA'	Primary Mkt Section by note *	Fund Manager	Ed and Administrator : On the recommendation of Fund Manager, upto Rs. 40 crore for all schemes put together Advisory Board: On recommendation of Fund Manager and PMIC above Rs. 40 crore by EC/Board for all Schemes put together
		Company/Instrument Rating	Delegation
Purchase		A+ and below (or any equivalent ratings) and NBFCs rated below AAA	Advisory Board: On recommendation of the Fund Manager and Committee consisting of ED and Administrator for all schemes put together

	Company/ Instrument Rating	Delegation
Sale	All transactions like buyback of debt prepayment etc. irrespective of rating	Administrator : upto Rs. 40 crs. Advisory Board: beyond Rs. 40 crs. On recommendation of Fund Manager and Internal committee.
	Put option on securities	Administrator : upto Rs. 40 crs. Advisory Board: beyond Rs. 40 crs. On recommendation of Fund Manager and Internal committee

Exposure Norms

It is also proposed that the exposure in a single NBFC may be limited to a maximum of the Networth of the NBFC as per the latest audited balance sheet, for all future investments (as against the earlier cap of Rs. 100 crore per NBFC). Networth for this purpose may be computed as:

Networth = Paid up Share Capital + Reserves and Surplus (excluding Revaluation Reserves) - Miscellaneous Expenditure not written off - Accumulated Losses, if any.

It is also clarified that investment in NBFCs excludes investment in Housing Finance Companies (for which there are separate norms) and Tier II Bonds issued by Banks.

2. SECONDARY MARKET INVESTMENT (Debt-other than govt. securities):

Purchases : The powers applicable will be per company per day.

Company/Instrument rating	Scrutiny	Recommended by	Approving authority
AA- and above (or any equivalent ratings)** and NBFCs with credit rating only 'AAA'	Office note by Secondary Mkt Section (debt) (detailed in part B of the memorandum)	Fund Manager	Fund Manager : Upto 2% of Assets under Management of a scheme Or Rs. 5 crore for a scheme Whichever is lower. Committee consisting of Executive Director and Administrator : On recommendation of Fund Manager, Upto 5% of Assets under Management of a scheme Or Rs. 20 crore for a scheme whichever is lower. Advisory Board : On recommendation of Fund Manager Above Rs. 20 crore for a scheme
A + and below (or any equi. Ratings) and NBFCs below rating of AAA	Detailed note by Secondary Mkt. Section (debt)****	Fund Manager	Advisory Board On recommendation of Fund Manager
Non-Investment Grade (other instrument without rating)	Detailed note by Secondary Mkt. Section (debt)**** (detailed in part B of the memorandum)	Fund Manager	Advisory Board On recommendation of Fund Manager

Sales : The powers applicable will be per company per day.

Company/Instrument Rating	Scrutiny	Recommended by	Approving authority
AA-and above (or any equivalent ratings)**	Office note by Secondary Mkt. Section (debt) (detailed in part B of the memorandum)	Fund Manager	Fund Manager : Upto 2% of Assets under Management of a scheme Or Rs. 5 crore for a scheme whichever is lower. Committee consisting of Executive Director and Administrator : On recommendation of Fund Manager, Upto 5% of Assets under Management of a scheme Or Rs. 20 crore for a scheme whichever is lower. Advisory Board : On recommendation of Fund Manager Above Rs.20 crore for a scheme
A + and below (or any equi. Ratings) and NBFCs securities of all ratings	Detailed note by Secondary Mkt Section (debt)****	Fund Manager	Fund Manager : Upto 2% of Assets under Management of a scheme Or Rs. 5 crore for a scheme whichever is lower. Committee consisting of Executive Director and Administrator : On recommendation of Fund Manager, Upto 5% of Assets under Management of a scheme Or Rs. 20 crore for a scheme whichever is lower. Advisory Board : Above Rs. 20 crore for a scheme On recommendation of Fund Manager

Amounts mentioned are in face value except in case of discounted bonds where cost of acquisition shall be considered for the purpose.

In case the proposal is for purchase of securities of NBFC the same is put up to the Advisory Board for its approval.

In case the yields at which the recommendation is made is lower/higher for purchases/sales than the yields mentioned for the corresponding rating and modified duration in the matrix used for valuation, at the time of taking decision, the same is approved by the next higher authority as per the delegation.

****The secondary market section does the financial analysis, indicate default status, adherence to the financial norms as prescribed for primary market Investments and regulatory requirements and explicitly state their views on the company's financials.

Execution in Secondary Market : (for UTI-1 as a whole)

Secondary market transactions (other than equity)	AGM	GM	ED
For UTI-1 as a whole per company per day	Rs. 10 crore	Rs. 25 crore	> Rs. 25 crore

1. GOVERNMENT SECURITIES

For the investments in Central Government Securities both through primary and secondary route ten times the amount limits as mentioned under the secondary market investment (debt) shall be applicable with % limits of Assets under Management remaining the same.

Central Government Securities per day : Primary and Secondary Market : Purchase and Sales combined**Approving authority****Fund Manager :**

Upto 4% of Assets under Management of a scheme

Or Rs. 20 crore for a scheme whichever is lower.

Committee consisting of Executive**Director and Administrator :**

On recommendation of Fund Manager, Upto 10% of Assets under Management of a scheme

Or Rs. 100 crore for a scheme whichever is lower.

Advisory Board :

On recommendation of Fund Manager
Above Rs. 100 crore for a scheme

For the investments in State Government Securities both through primary and secondary route five times the amount limits as mentioned under the secondary market investment (debt) shall be applicable with % limits of Assets under Management remaining the same.

State Government Securities per day**Approving authority****Fund Manager :**

Upto 4% of Assets under Management of a scheme

Or Rs. 10 crore for a scheme whichever is lower.

Committee consisting of Executive**Director and Administrator :**

On recommendation of Fund Manager, Upto 10% of Assets under Management of a scheme

Or Rs. 50 crore for a scheme whichever is lower.

Advisory Board :

On recommendation of Fund Manager
Above Rs. 50 crore for a scheme

The Fund Manager ensures that all the investment decisions are based on each fund's liquidity, investment objectives, internal guidelines and regulatory restrictions.

Others

The Inter Scheme Transfers of assets are akin to a secondary market transfer of assets which are based on the current valuations/prices. They do not lead to any fresh exposure for the UTI-I. Hence, the delegation for Inter Scheme Transfers for companies rated AA-and above and 'AAA' rated NBFCs would be the same as applicable for secondary market transactions. The Inter Scheme Transfers of NBFCs other than 'AAA' rated and papers rated A+ or below but which are of investment grade are to be approved by Administrator.

(B) DECISION MAKING PROCESS/RECORDING OF INVESTMENT DECISIONS :

Details as per Chapter III of Manual of Investment Policies, Guidelines and Risk Control Framework.

(C) REPORTING :

A report on the investments made is put up by the primary market section/secondary market section to the Executive Directors and Administrator on a daily basis for information. A summary of the same is also be placed for the information of Advisory Board on a regular basis.

(D) NCONTROL AND CORRECTIVE ACTIONS :

The above listed delegation of power are controlled through a system driven mechanism (when introduced) whereby checks and balances are established to ensure strict adherence to delegation of power.

If by any chance, there is a non-adherence at any level i.e., the transacted amount exceeds the delegated authority, it is immediately reported to the competent authority to seek ratification.

[F. No. 5/6/2003-UTI & JPC]

U.K. SINHA, Jt. Secy.

ANNEX B

DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

[See section 4(4)]

I do hereby declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as Administrator or Adviser of the Administrator of the Specified Undertaking of Unit Trust of India (Specified Undertaking) and which relate to the office or position held by me in the said Specified Undertaking.

I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the Specified Undertaking or to the affairs of any person having any dealing with the said Specified Undertaking; nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to or in the possession of the Specified Undertaking and relating to the business of the said Specified Undertaking or the business of any person having any dealing with the said Specified Undertaking.

Signed before me :

(Signature)